पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016

+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 28 अप्रैल 2024

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

अभाविप ने यूजीसी एवं एनटीए को पत्र लिखकर यूजीसी-नेट परीक्षा तिथि के संशोधन के लिए की माँग

यूजीसी-नेट परीक्षा की तिथि में संशोधन करने हेतु अभाविप ने दिया ज्ञापन; एक ही तिथि पर आयोजित हो रही यूपीएससी एवं यूजीसी-नेट परीक्षा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पत्र लिखकर यूजीसी-नेट परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 16 जून 2024 को संशोधित करने की माँग की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी की परीक्षा भी इसी तिथि पर होने से छात्रों को गंभीर समस्या से बचाने के लिए अभाविप ने यह माँग यूजीसी एवं एनटीए से की है।

उल्लेखनीय है कि, एनटीए ने दिनांक 20 अप्रैल 2024 को अपने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यूजीसी - नेट जून 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है एवं इस परीक्षा की तिथि 16 जून 2024 प्रस्तावित की है। साथ ही इससे पूर्व ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिनांक 19 मार्च 2024 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से Civil Services (Preliminary) Examination, 2024 की परीक्षा इसी तिथि 16 जून 2024 को निश्चित की है। यूपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कई अभ्यर्थी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी - एनईटी जून 2024 में भी शामिल हो रहे हैं एवं एक ही परीक्षा तिथि होने के कारण छात्रों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को पत्र लिखकर शीघ्र ही परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की है, ताकि छात्र ससमय असुविधा से बच सकें।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा, "अनेक विद्यार्थी यूपीएससी एवं यूजीसी - एनईटी दोनों ही परीक्षाएं देते हैं। एक ही तिथि होने से तैयारी के अंतिम क्षणों में असमंजस उत्पन्न होना छात्रों के भविष्य एवं मनःस्थिति दोनों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। इसी हेतु अभाविप ने यूजीसी एवं एनटीए को पत्र लिखकर यूजीसी-नेट की प्रस्तावित तिथि में परिवर्तन करते हुए तत्काल इस सम्बन्ध में घोषणा करने की माँग की है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गयी है।)